जनगर्जन

वर्ष 25 अंक 7 मासिक नई दिल्ली मार्च-2011 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

वोट के बदले नोट घोटाला: संप्रग सरकार पर घूसखोरी आरोप की अपराधिक जाँच जरूरी

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में 2जी स्पेक्ट्रम जैसा महाघोटाला, राष्ट्रमण्डल खेलों एवं अन्य बड़े घोटालें सामने आये, इसके तुरन्त बाद विक्लीक्स के जरीये, द हिन्दू (दैनिक पत्रिका – अँग्रेजी) में 17 मार्च 2011 को प्रकाशित समाचार के कारण भयावह स्थिति हो गयी। उक्त समाचार के अनुसार भारत अमेरिकी नाभिकीय समझौते के ऊपर जुलाई 2008 में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर विजय हासिल करने के लिये संप्रग सरकार ने सांसदों को भारी रिश्वत दी थी। उक्त समाचार के प्रकाशित होते ही पूरे देश में और संसद में भूचाल आ गया। समूचा विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तुरन्त जवाब मांगने लगा और विक्लिक्स के जरिये हुये इस खुलासे पर टिप्पणी करने का आग्रह करने लगा। कांग्रेस को उक्त प्रकरण में पूरी तरह से लगे आरोपों को खारिज करने में एक दिन का समय लग गया। उनके उत्तर पर पूरा विपक्ष असंतुष्ट था और इस मामले में अविलम्ब अपराधिक जाँच की मांग करने लगा। विक्लिक्स ने वही उजागर व सुनिश्चित भी किया जो जुलाई 2008 की घटना के बाद वाम दल लगातार कह रहे थे। स्पष्ट रूप से विपक्ष ने घूसखोरी के इस जघन्य कृत्य की पर तीखा प्रहार करते हुये कहा कि इस तरह कांग्रेस ने संसदीय लोकतंत्र की हत्या कर डाली है और अब उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है।

सरकार का यह तर्क है कि घूस का यह मामला चौदहवीं लोकसभा का है और उसे वर्तमान पन्द्रहवीं लोकसभा में चर्चा के लिये नहीं लाया जा सकता। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यह वही कांग्रेस नीत संप्रग सरकार है जो जुलाई 2008 में भी सत्ता में थी और वही प्रधानमंत्री आज भी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस तरह ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और इस तरह सरकार की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस मसले पर सही कदम उठाये। यदि वे पाक साफ है कि तो इसे सिद्ध करें। वर्ष 2008 में संसदीय जाँच समिति बनी जिसके अगुवा किशोर चन्द्रदेव थे। इस समिति का कहना है कि घूस का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उपलब्ध प्रमाण अपर्याप्त हैं। परन्तु और अधिक जाँच का कार्य उस वक्त भी आगे बढ़ाया जा सकता था। वर्तमान विक्लिक्स के चौका देने वाले तथ्यों जिनके अनुसार विश्वास मत प्राप्त करने के लिये सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिये पचास से साठ करोड़ रुपये दिये गये थे और सत्ताधारी दल के कुछ लोगों का नाम घूस प्रबन्धन में सामने आने के बाद सीबीआई द्वारा अपराधिक जाँच सरकार को अविलम्ब करवाना चाहिये। परन्तु ऐसा यह सरकार तभी करेगी जब उसे इस प्रकरण में पारदर्शिता साबित करने में रूचि हो।

प्रधानमंत्री महोदय का दिया गया बयान तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है कि संप्रग ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की है और इस तरह 2008 में बनी केशव चन्द्र देव जाँच समिति द्वारा अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर घूस के लगे आरोप सिद्ध नहीं किये जा सकते है।

विपक्षी दलों के हार और सम्प्रग की जीत 2009 लोकसभा चुनाव में हुई इस हार-जीत के ऊपर विस्तृत राजनैतिक विश्लेषण के जरिये सैकड़ों कारण गिनाये जा सकते है। वोट के बदले नोट घोटाला अकेला चुनावी मुद्दा नहीं था, चुनाव के बाद भी यह घोटाला जीवंत रहा और विक्लिक्स के जरिये जग-जाहिर हो चुका है। विपक्षी दलों के लगातार कड़े तेवर और दबाव के बाद 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले के ऊपर सरकार किसी तरह संयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिये तैयार हो गयी। हमें अब इस बात पर आश्चर्य है कि कितने और राजनैतिक आन्दोलन के बाद सरकार सीबीआई के द्वारा वोट के बदले नोट घोटाले की जाँच करवाने के लिये तैयार होगी। यदि सरकार इस प्रकरण में नैतिक और आचार सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी से बचती है तो अपने पारदर्शी प्रशासन के दावे से कोसों दूर हो जायेगी। इस तरह हम अविलम्ब अपराधिक जाँच इस घोटाले में सीबीआई जाँच की मांग करते हैं और सरकार को इस प्रकरण को बन्द करने की इजाजत नहीं दे सकते है।

भूकंप और सुनामी प्रभावित जापान पर नाभिकीय विपदा: भारत को इससे सबक लेने की आवश्यकता

जापान और दुनिया की कई अन्य भागों में 11 मार्च 2011 को रिक्टर पैमाने पर 8.9 स्तर का भयानक भूकंप आया और साथ में सुनामी भी आया। भूकंप के आने से 10 मीटर ऊँची समुद्री लहरों के सुनामी की चपेट में जापान आया। इस सुनामी के रास्ते में आने वाले घर, नाव, जहाज, ट्रेन और कार शहरों समेत तबाह हो गये। तटीय इलाके में स्थित खेत और बन्दरगाह नष्ट हो गये। साथ में वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट भी हो चुका है।

हजारों लोग मारे गये और हजारों की संख्या में लापता भी बताये गये। विध्वंस जिस स्तर का देखा गया है उससे अनुमान लगाया गया कि मरने वालों की संख्या 10,000 से भी भी हो सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर मूलभूत ढाँचे को क्षति पहुँची और जापान के उत्तरी पूर्वी तट तथा समीपवर्ती शहरों की संपदा नष्ट हो गयी। इस भूकंप के कारण जापान के अनेक जगहों में आग लग गई। ये सभी घटनायें प्राकृतिक विपदा जिसमें मनुष्य लाचार और बौना बनकर रह गया।

इस विपदा की विनाश लीला के दूसरे भाग पर गौर करें जो कहीं ज्यादा भयावह है। नाभिकीय संयंत्रों के भयावह विस्फोट की संभावनायें जिनसे निकलने वाले विकीरण जापान के विशाल जन समुदाय को प्रभावित कर रही हैं। जापान के उत्तर पूर्वी छोर पर फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र है। वहाँ विस्फोट हुआ और संयंत्र नियंत्रण के बाहर हो चुका है। उक्त संयंत्र से भारी मात्रा में विकीरण हो रहा है। और सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जापान इतनी बड़ी विभीषिका झेल रहा है यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फुकुशिमा से होने वाली क्षति रूस के चेरनॉनविल में हुये नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना से भी अधिक विनाशकारी है।

फुकुशीमा नाभिकीय संयंत्र में हुये विस्फोट से भारत को तुरन्त सबक लेना चाहिये। भारत के पास 20 संयंत्र है और अधिकाश समुद्री तट पर स्थित है। जपान की तरह आये सुनामी भारत के तट पर कब आ जाये कोई नहीं कुछ कह सकता और नाभिकीय दुर्घटनायें कभी भी हो सकता है। हम केन्द्र सरकार से व उसके परमाणु उर्जा विभाग से मांग करते है कि भारत के नाभिकीय संयंत्रों का तुरन्त मुआयना किया जाये और आने वाली ऐसी किसी विपदा से तुरन्त निपटने के लिये कारगर कदम उठाये जाये।

जब परमाणु उत्तरदायित्व विधेयक पर संसद में बहस हो रही थी उसी समय हम सभी वाम दलों ने नाभिकीय के सुरक्षा की समीक्षा और आवश्यकता पर प्रकाश डाला हम आज भी यह सुनिश्चित करना चाहते है कि जापान जैसी नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना को रोकने के लिये और शत् प्रतिशत सुरक्षित नाभिकी संयंत्रों की गारण्टी के आधार पर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिये। यही नहीं हमें बहुत ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा पर आश्रित नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसी किसी दुर्घटना के बाद पुरे देश में ऊर्जा संकट खड़ा हो जायेगा। इस तरह हमें गंभीरता पूर्वक नाभिकीय सयंत्रों की सुरक्षा के सभी पहलुओं की जाँच करनी चाहिये और तभी अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों जैसे जैतपुर (महाराष्ट्र), हरिपुर (पश्चिम बंगाल) और दूसरे स्थानों में नाभिकीय संयंत्रों को स्थापित करना चाहिये। हम सरकार से आग्रह करते है कि नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाये और राष्ट्र का विश्वास प्राप्त करने के लिये इस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करे।

रेलवे और केन्द्रीय बजट - 2011-12: एक अवलोकन

डॉ. बरूण मुखर्जी, संसद सदस्य

हम केन्द्रीय बजट 2011-12 की समीक्षा बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, गरीबी और खाद्य असुरक्षा जैसे ज्वलंत विषयों के परिदृश्य में करें। वित्तमंत्री प्रणवमुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस वर्ष हमारे बजट का मुख्य विषय बढ़ती हुई खाद्य वस्तुओं की कीमतें है। स्वभाविक है कि जनता को बजट से काफी आशायें व उम्मीदें थी परन्तु दुर्भाग्य है कि उनकी आशायें मटियामेट हो गयी।

सरकार की मंशा खाद्य वस्तुओं की कीमत को नियन्त्रित करने की अवश्य रही है। परन्तु इस संदर्भ में कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। खाद्यान्न और अन्य आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के क्षेत्र में जारी वायदा करोबार और पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाला अधिभार जारी रहा। यदि इन पर कड़ी कार्यवाही हुई तो कीमतों को नियन्त्रित करना कुछ आसान हो गया होता। सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये विनिवेश के द्वारा प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया था। यह लक्ष्य लाभ कमाने वाली सार्वजनिक उपक्रमों को जनता की भागीदारी के नाम पर उगारी करना था। निश्चित रूप से इससे देश की अर्थव्यवस्था और संसाधन बुरी तरह प्रभावित होंगे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल (पीपीपी मॉडल) की शुरूआत के नाम सरकार की बुरी मंशा है कि इन सभी प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर दिया जाये।

बजट में देखा गया कि बड़े कारपोरेट घरानों को भारी मात्रा में आयकर में छूट दी गयी है, जबकि ये घराने आसानी से कर दे सकते हैं। यह तथ्य

साबित हो चुका है कि सिलसिलेवार तरीके से विगत कुछ वर्षों से इन घरानों का मुनाफा तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2005-06 में 4.08 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 8.28 लाख करोड़ हो गया। इतना मुनाफा कमाने के बावजूद कारपोरेट जगत को कर में छुट भी खूब बढ़ाई गयी। कर में छूट वर्ष 2005-06 में 34,618 करोड़ से बढ़ाकर वर्तमान वर्ष में 88,263 करोड़ कर दी गयी। आश्चर्य तो इस बात का है कि वर्तमान बजट में इन घरानों को कर में छूट तब दी गयी है जब भारी राजस्व घाटा 4,12,817 करोड़ रुपये का देश भुगत चुका है। कारपोरेट घरानों को दी गयी कर में छूट के विषय पर किसी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कारपोरेट जगत को औसतन 240 करोड़ रुपये प्रतिदिन की दर राहत जारी है। जबकि इतनी ही धनराशि भारत से प्रतिदिन काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जा रही है।

कस्टम और उत्पाद शुल्क में उल्लिखित राजस्व से भी कारपोरेट और सुविधा संपन्न लोगों को ही लाभ पहुँचेगा।

वहीं दूसरी तरफ खाद्य, ईंधन, खाद में आदि में दी जाने वाली कटौती आम आदमी की तकलीफों को और अधिक बढ़ायेगी। यह वह नीति है जो गरीब जनता को साथ लेने की बजाय उसे हाशिये पर धकेलने की है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आबंटित धन में वृद्धि स्वागत योग्य है। परन्तु सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों में धन आबंटन की सख्त जरूरत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सेवाओं में शामिल कर लेना चाहिये और शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलु उत्पाद का 6 प्रतिशत भाग आबंटित होना चाहिये।

कृषि और संबंधित सहयोगी गतिविधियों के कार्यक्रमों में वर्ष 2010-2011 की धनराशि 14,361.55 करोड़ को थोड़ा सा बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 14,744.15 करोड़ रुपये किया गया। यह संरचनात्मक कदम नहीं है और खाद्य वस्तुओं की कीमतों की रोकथाम में अक्षम है।

सारांश में सरकार का केन्द्रीय बजट उसकी नवउदारवादी आर्थिक नीति को उजागर करता है जिसमें धनी को और धनी बनाने की सुविधा उपलब्ध है और बहुप्रचारित आम आदमी तथा समग्र विकास के नारे को समाहित करने वाला यह बजट कदापि नहीं है। बढ़ती कीमतों को वापस कम करने में और विशाल आबादी के अभाव को दूर करने के लक्ष्य से यह बजट कोसो दूर हैं।

रेलवे बजट 2011-2012 भी लक्ष्य और दिशाविहीन है। यह प्रचार मात्र पर आधारित बजट है जिसमें रेलमंत्री की निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव पर टिकी हुई है न कि रेल यात्रियों, पटरियों और ट्रेनों की सुरक्षा के व्यापक कार्यक्रम पर। रेलमंत्री के बजट में घोषणायें तो होती है परन्तु उन पर क्रियान्वयन नहीं होता है। ऐसा पिछले 3 बजटों से देखा जा रहा है। उन्हें 'घोषणा मंत्री' कहना ज्यादा अच्छा होगा। पिछले वर्ष 1320 मेगावाट क्षमता का थरमल पॉवर संयंत्र पश्चिम बंगाल के अदरा में स्थापित करने की घोषणा की गई थी जो अभी भी अपने प्रारम्भिक दौर है। उन्होंने 800 किलोमीटर तक छोटी लाईन को बड़ी में परिवर्तित करने का लक्ष्य घोषित किया था, 700 किलोमीटर तक दोहरी लाईन और 1000 किलोमीटर विद्युतिकरण की घोषणा की गयी थी। ये सारे कार्य आज तक शुरू ही नहीं हुये। रेलवे को इम्फाल तक बढ़ा दिया जायेगा और मणिपुर में डीजल लोकोमोटिव केन्द्र स्थापित होगा - महज प्रस्ताव बनकर रह गये। 236 आदर्श स्टेशन हाल में प्रस्तावित हुये, परन्तु इनको हासिल करने की कोई तिथि नियत नहीं की गयी। पिछली घोषणायें अभी तक पूरे नहीं हुये। पूर्व में घोषित 'विश्व स्तरीय स्टेशन' के मामले में बढ़ती कीमतों के कारण ज्यादा कुछ नहीं हो सका। अपने क्षेत्र में ध्यान लगाने की बजाय रेलमंत्री ने बहुत सी घोषणायें की जैसे अस्पताल के भवन का निर्माण, नर्सिंग होम्स, केन्द्रीय विद्यालय, आवासीय कॉलेज, खेल अकादमी और स्टेडियम, कई मेडिकल कॉलेज, बॉटलिंग प्लांट इत्यादि हमेशा की तरह कहा बहुत कुछ गया और हुआ कुछ भी नहीं। अगर कुछ हुआ भी तो सोनिया गाँधी के चुनाव क्षेत्र में कोच वेगन (रेल के डिब्बे) बनाने की फैक्टरी का कार्य प्रगति में है। एक तरफ रेलमंत्री यह घोषणा करता है कि वह फिजुल खर्जी रोकने के सारे कदम उठा रहा है वहीं अल्पसमय में ही की गई घोषणाओं के शिलान्यास के कार्यक्रमों में भारी राशि लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये। जो आवश्यक कार्य जैसे दुर्घटना रोकने वाले यंत्र, रेल क्रासिंग (फाटक) पर कर्मचारियों की नियुक्ति और रेल और स्टेशनों के नियमित उचित रख-रखाव जैसे कार्य उपेक्षा के शिकार है।

सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि रेलमंत्रालय का वित्तीय व्यवस्था चरमरा उठी है। जिसे रेलमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा भी है कि भारतीय रेल बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। फिर भी वे किसी ठोस नतीजे और कार्यक्रम बनाने में असफल क्यों है। अप्रैल - अक्तूबर 2010 में रेलवे राजस्व की निर्धारित लक्ष्य राशि में 1192 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वहीं कार्यकारी खर्चे 2400 करोड़ हो गया है। कुल घाटा राजस्व का 3600 करोड़ रुपये है। यदि बजट अनुदान को देखा जाये तो यह घाटा 2200 करोड़ रुपये का है। लाभांश में भारी कमी हुई है और अस्थिरता भी आई है। रेल बजट वित्तमंत्री के विशाल अनुदान पर टिका हुआ है। पारंपरिक रूप से रेलमंत्रालय आम बजट में अच्छी खासी धनराशि दिया करती थी उस समय हमारा रेल मंत्रालय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक धरोहर था, परन्तु अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ बन चुका है।

रेल पास के लिए मजदूरों का प्रदर्शन

रेलमंत्री की घोषणा के बावजूद बिहार में नहीं मिला पास

रेलमंत्री की घोषणा के बावजूद बिहार में एक भी देहारी मजदूर को इज्जत पास नहीं दिया गया है। उक्त बातें ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेन्टर बिहार राज्य महासचिव साथी वकील ठाकुर ने प्रदर्शन सभा में कहा। उन्होंने कहा कि रेलमंत्री ममता बनर्जी की यह घोषणा झूठ साबित हुई है। इसके पूर्व अपने विभिनन मांगों को लेकर संगठन से जुड़े दर्जनभर असंगठित मजदूरों के संगठन अग्रगामी मजदूर असंगठित कामगार संघ, बिहार स्लम विकास समिति, अग्रगामी मजदूर अंसगठित मजदूर यूनियन, अग्रगामी पथ परिवहन यूनियन, फूटपाथ दुकानदार संघों से जुड़े मजदूरों ने गुलजारबाद रेलवे स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सेंटर के प्रदेश सचिव विरेन्द्र ठाकुर ने की। इसके पूर्व मजदूरों ने पटना नगर निगम सिटी अंचल से जुलूस प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि जब से ममता बनर्जी रेलमंत्री बनी हैं तब से ट्रेनों का परिचालन भी विलंब हो गया है। जब ममता बनर्जी से रेल मंत्रालय नहीं संभल रहा तो बंगाल में सरकार बनाने की बात करना जनता को धोखा देना है। उन्होंने शीघ्र ही बिहार में मजदूरों को इज्जत पास देने की मांग रेल मंत्री से की। सभा को माकपा शहर कमेटी के सदस्य विनय कुमार सिन्हा, राजेश कुमार, प्रेम कमार, सावित्री देवी, कामंती देवी, नीलम देवी, जिला सचिव परशुराम प्रसाद, नथुनी आदि ने भी संबोधित किया।

विधान सभा चुनाव के लिये फारवर्ड ब्लॉक तैयार

दक्षिणपंथी ताकतों एवं वामविरोधी ताकतें, जिन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिये, धन-बल आदि के सभी हथकंडे अपना रही है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। उन्हें जवाब देने के लिये फारवर्ड ब्लॉक ने इन ताकतों को करारा जवाब देने के लिये विशेष कदम उठायें है जिसके तहत अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में उन प्रतिनिधियों को उतारा हैं जो दक्षिणपंथी ताकतों से कारण जनता की समस्या और उनकी तकलीफों के प्रति उनकी आवश्यकता एवं उनके निवारण हेतु उनके साथ उनकी अकांक्षाओं पर खरे उतरने के योग्य है। प्रतिनिधियों के चयन प्रक्रिया में पार्टी ने अपने पिछले विधानसभा के चुनाव में विजयी उम्मीदवरों में बदलाव किया है तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक जनप्रिय उम्मीदवारों को जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुनाव मैदान में उतारा है।

इस दौर में पश्चिम बंगाल में फारवर्ड ब्लॉक ने जहाँ वर्तमान 8 विधायकों को बैठाया है वहीं 15 नये उम्मीदवरों का चयन किया है जिनमें 4 महिला, 9 अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति तथा 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में फारवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधी वामफ्रंट के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ेंगे।

आसाम में फारवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधी वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआई (एम), और सीपीआई (एमएल) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी।

पश्चिम बंगाल में पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी 34 उम्मीदवार खड़े कर रही है। उनके पूर्ण विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	नाम	क्षेत्र (जिला सहित)	अनु./अनु.ज. जाति	मुस्लिम	म./पु.	नये
1.	परेश चन्द्र अधिकारी	मेखलीगंज (कूचबिहार)	अनु. जाति	-	पु.	-
2.	नगेन रॉय	कूचबिहार उत्तर	अनु.	-	पु.	नया
3.	अक्षय ठाकुर	कूचबिहार दक्षिण	-	-	पु.	
4.	दिपक रॉय	सिताई (कूचबिहार)	अनु.	-	पु.	नया
5.	उदयन गुहा	दिनहाटा (कूचबिहार)	-	पु.	-	
6.	गोबिन्द रॉय	जलपाईगुड़ि	अनु.	-	पु.	-
7.	सफिउर रहमान	गोलपोखर (उ. दिनाजपुर)	-	मु.	पु.	नया
8.	अली इमरान रम्ज (विक्टर)	चकुलिया (उ. दिनाजपुर)	-	मु.	पु.	-
9.	गोकुल रॉय	करांदिघी (उ. दिनाजपुर)	-	-	पु.	-

10.	तजमुल हुसैन	हरीशचन्द्रपुर (मालदा)	–	मु.	पु.	–
11.	मकसुदा बेगम	रानीनगर (मुर्शिदाबाद)	–	मु.	म.	नया
12.	विभास चक्रवर्ती	मुर्शिदाबाद	–	–	पु.	–
13.	मृणाल सिकदार	बाग्दा (उ. 24 परगना)	अनु.	–	पु.	नया
14.	हरिपद बिश्वास	जगादल (उ. 24 परगना)	–	–	पु.	–
15.	रंजीत चौधरी	मध्यमग्राम (उ. 24 परगना)	–	–	पु.	नया
16.	संजीब चटर्जी	बारासात (उ. 24 परगना)	–	–	पु.	नया
17.	डॉ. मुर्तजा हुसैन	देगंगा (उ. 24 परगना)	–	मु.	पु.	–
18.	माइनुद्दीन शम्स	कोलकाता पार्ट	–	मु.	पु.	–
19.	जिवन शाहा	श्यामपुकार (कोलकाता)	–	–	पु.	–
20.	डॉ. जगन्नाथ भट्टाचार्य	सिबपुर (हावड़ा)	–	–	पु.	–
21.	डोली रॉय	पांचला (हावड़ा)	–	–	म.	–
22.	शेख कुतुबुद्दीन अहमद	उलुबेरिया दक्षिण (हावड़ा)	–	मु.	पु.	नया
23.	मिनाति प्रमाणिक	श्यामपुर (हावड़ा)	–	–	म.	नया
24.	नरेन दे	चुचुरा (हुगली)	–	–	पु.	–
25.	सरबानी सरकार	धनीयाखाली (हुगली)	अनु.	–	म.	नया
26.	विश्वनाथ कारक	गोघाट (हूगली)	अनु.	–	पु.	नया
27.	मंगल महतो	बागमुण्डी (पुरूलिया)	–	–	पु.	नया
28.	धिरेन महतो	जयपुर (पुरूलिया)	–	–	पु.	नया
29.	तारापद चक्रवर्ती	ओण्डा (बांकुरा)	–	–	पु.	–
30.	सुनील कुमार मण्डल	गोलसी (बुर्दवान)	अनु.	–	पु.	नया
31.	मणिकलाल आचार्य	कुल्टी (बुर्दवान)	–	पु.	–	
32.	विजय बग्धि	दुब्राजपुर (बिरभूम)	अनु.	–	पु.	–
33.	रेबाती रंजन भट्टाचार्य	रामपुरहॉट (बिरभुम)	–	–	पु.	नया
34.	दिपक चटर्जी	नालहाटी (बिरभुम)	–	–	पु.	–

फारवर्ड ब्लॉक के आसाम प्रतिनिधियों की सूची

1.	फिडल चौधरी	सोनाई
2.	डिम्पुल सोनोवाल	धेमाजी
3.	राजकुमार डोवाराह	अमगुरी
4.	होरेन बोरगोहेन	महमारा
5.	इन्द्रेश्वर गेरोई	थोवरा

23 मार्च: शहीद–ए–आज़म भगत सिंह को श्रद्धांजलि

वैचारिक–राजनैतिक–सामाजिक क्रांति भगत सिंह के रास्ते

प्रभा शंकर मिश्र

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक महान सपूतों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। परन्तु उनमें भी शहीद–ए–आजम भगत सिंह का अप्रतिम स्थान है। देश को तथाकथित आजादी तो मिल गई परंतु दशक दर दशक से देश की उस विशाल आबादी का शोषण जारी है जो सबसे पहले सही मायने में आजादी की हकदार रही है। पूँजीवाद–साम्राज्यवाद अपने परिमार्जित रूप में देश को अपने चंगुल में जकड़े हुए है। ऐसी परिस्थिति में भगत सिह के बलिदान की प्रासंगिकता एकमात्र विकल्प बनकर उभरती है।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गाँधी के समानांतर भगत सिंह की बेहद लोकप्रियता थी और अपने छोटे से जीवन–काल में उनके चाहने वालों में गाँधी के नजदीकी अनेक गणमान्य कांग्रेसी भी थे।

भगत सिंह अपने प्रारंभिक दिनों में महात्मा गाँधी के प्रशंसक और अनुयायी थे। गाँधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। वे श्रद्धापूर्वक गाँधी के नेतृत्व को मानते थे और विश्वास करते थे कि एक दिन अवश्य हम सभी गाँधी के नेतृत्व में आजादी हासिल कर लेंगे। वर्ष 1922 में चौरी चौरा काण्ड के बाद जब गाँधी ने आंदोलन वापिस ले लिया तो उनका गाँधीवाद से मोह भंग होने लगा। शनैः शनैः उनका दृष्टिकोण क्रान्तिकारी संघर्ष की तरफ विकसित होने लगा। अपनी गिरफ्तारी और शहादत के पूर्व तक अनेक साहसी कारनामों को अंजाम देकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को गहरे आघात दिए वहीं एक क्रांतिचेता के रूप में भारतीय जनमानस को कहीं बहुत गहरे तक उद्वेलित करने में सफलता प्राप्त की।

गाँधी और गाँधीवाद तथा कांग्रेस के तौर तरीकों से अनेक अवरोध पाने के बावजूद भगत सिंह व्यक्तिगत रूप से गाँधी का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें एक भद्र पुरूष तथा मानवतावादी कहा करते थे। जबकि गाँधी स्वयं भी भगत सिंह के प्रशंसक होने का दावा करते थे और सार्वजनिक सुअवसरों पर उनके देशभक्ति की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे परंतु जब उन्हें उनके साथियों समेत फाँसी की सजा हुई तब गाँधी ने ब्रिटिश अधिकारियों एवं व्यवस्था से अच्छा तालमेल एवं प्रभाव रखने के बावजूद वायसराय को पत्र लिखकर इन महान सपूतों को मिली सजाा को अनुमोदन किया।

हिंसा या अहिंसा:

हिंसा या अहिंसा इस प्रश्न पर भगत सिंह की विचारधारा स्पष्ट थी। उनका कहना था कि हिंसा रूपी बल का प्रयोग अन्याय करने के लिये होता है जो क्रांतिकारियों को नापसन्द है। वहीं अहिंसा का प्रयोग आत्मारूपी बल से है जिससे आत्मपीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है, वह भी इस आशा से कि विरोधी इस प्रक्रिया को देखकर अपना विचार बदल देगा और आपकी बात समझने की अवस्था में आ जाएगा। वहीं जब एक क्रांतिकारी कुछ विषयों पर आवश्वस्त हो जाता है तो अपने अधिकारों की माँग करता है, अनुरोध करता है, तर्क करता है, प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करता है और यह सब अपने प्रभावकारी आत्मा रूपी बल के नेतृत्व में करता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भयावह यातनाएँ सहने को सहर्ष तैयार रहता है तथा साथ ही उच्चतम बलिदान देने को तत्पर रहता है और यह सब अपने भौतिक सम्पूर्ण सामर्थ्य रूपी बल के सदुपयोग से करता है। आप क्रांतिकारियों के तौर तरीकों को चाहे जो संज्ञा दे परन्तु उसे हिंसा शब्द से नहीं समझ सकते हैं।

सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह है। मात्र आत्मारूपी बल के द्वारा ही ऐसा आग्रह क्यों ?उसमें शारीरिक सामर्थ्य रूपी बल का साथ में प्रयोग क्यों नहीं कर सकते ?वहीं आजादी हासिल करने का क्रांतिकारी का मार्ग अलग है। उसे आत्मारूपी बल के साथ नैतिक और शारीरिक बल को संपूर्ण मात्रा में झोंक देने में रत्तीभर परहेज नहीं होता है। इस तरह प्रश्न महज हिंसा का नहीं है, वरन् उसमें आत्मा और शारीरिक दोनों के मिश्रण से उत्पन्न बल का है।

देश की आजादी किसके नेतृत्व में हासिल की जाए इस बारे मं भी भगत सिंह की राय बेबाक थी। उनका कहना था कि देश की आजादी क्रांतिकारियों के नेतृत्व में मिलनी चाहिए। हम जिस क्रांति के लिए आशापूर्ण तरीके से संघर्षरत हैं उसको महज इस रूप में नहीं देखना चाहिये कि यह सशस्त्र संघर्ष विदेशी सरकार और उसके समर्थकों के साथ भारतीय जनता का है। यह संघर्ष एक नए सामाजिक समीकरण की स्थापना का है। यह क्रांतिकारी संघर्ष पूँजीवाद, वर्ग अंतर और सुविधाभोगियों के लिए का बनकर बरपेगा। वहीं यह संघर्ष करोड़ों सुविधा विहीन, भूखे तड़पते भारतीयों के लिए खुशी और समृद्धि का कारण बनो और उसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद तथा उनके पिट्ठू देशी शोषकों के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। हमारा मार्ग इसी तरीके से राष्ट्र निर्माण करेगा। जिसमें एक नए राज्य का जन्म होगा जहाँ वर्ग विहीन समाज होगा और सर्वहारा प्रतिष्ठित होगा। ऐसे समाज में राजनीति शक्ति के द्वारा सामाजिक विषमता के संक्रमण का सफाया कर दिया जाएगा। क्रांतिकारी सफलता की प्राप्ति के लिए अपने मार्ग का निर्धारण अपने तरीके से खुले आम और गोपनीय रूप में करते हैं। क्रांतिकारियों के पास दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में शोषक सत्ता वर्ग एवं मेहनतकश मुक्तिकामी जनता के बीच चलने वाले संघर्षो का अनुभव जन्य इतिहास की थाती है जो हमारे संघर्षों का मार्ग दर्शन करता रहता है जहाँ सफलता प्राप्ति की मंजिल तक पहुँचने के पूर्व की असफलताएँ विचलित नहीं कर सकती।

एक तरफ जहाँ कांग्रेस का राजनैतिक संक्रमण स्वराज से पूर्ण आजादी की घोषणा के कलेवर में सामने आई थी वहीं कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार पर हमला करने के बजाए क्रांतिकारियों पर ही धावा बोल दिया। ऐसा पहला उदाहरण कांग्रेस ने 23 दिसम्बर 1929 को वायसराय स्पेशल ट्रेन हमले के प्रसंग पर लाहौर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में सामने आया। इस प्रसंग में क्रांतिकारियों के विरोध में गाँधी के द्वारा निर्मित प्रस्ताव के पक्ष में 904 और विपक्ष में 823 मत पड़े। प्रस्ताव महज 81 मतों से पारित हो तो गया परन्तु कांग्रेस में गाँधी के नजरिए से भिन्न क्रांतिकारियों के हिमायती लोग भी काफी थे। इस तरह कांग्रेस भी विभाजित थी।

अपनी मजबूत तर्किक क्षमता, प्रभावशाली वाक्क्षमता के साथ कई साहसपूर्ण कृत्यों से भगत सिंह भारतीय जनमानस में गहरे बैठ गए थे। दो घटनाएँ फिर भी महत्त्वपूर्ण हैं। लाला लाजपतराय की मृत्यु के लिये जिम्मेदार ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे पी सॉण्डर्स का वध और एसेम्बली में फेंके गए बम की घटना, जिस कारण उन्हें जीवन की बलि देनी पड़ी। उनके ऊपर चली कानूनी कार्यवाही तथा सुखदेव, राजगुरू के साथ फाँसी के फँदे को चूम लेने के बाद पूरा देश रो उठा, काँप उठा और चीत्कार कर उठा। कांग्रेस के भीतर गाँधी से अलग राय रखने वालों की भारी तादात थी। नेहरू और

सुभाष बाबू गाँधी से अलग राय रखते थे। नेहरू 'नोजवान भारत सभा' को भावी राष्ट्र के निर्माण की भूमिका में देखते थे और भगत सिंह के चमत्कृत व्यक्तित्व के कायल थे वहीं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उन्हें 'युवाओं में जागृति पैदा करने वाले नेता के रूप में देखते थे। जबकि गाँधी इन क्रांतिकारियों को भ्रमित युवा और शिथिल पड़ चुके विचार वाला और देश के दुश्मन के रूप में घोषित करने में संकोच नहीं किया। इनके महाना आत्मोत्सर्ग पर गाँधी कहते थे कि ये अबोध, अज्ञानी और भ्रमित युवा हैं, जिनका प्रयास निरर्थक और बेकार सिद्ध हो रहा है। और अपने क्रियाकलापों से ये लोग देश को पीछे ढकेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मोती लाल नेहरू, पुरूषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता और शैकत अली क्रांतिकारियों को राजनैथ्तक और आर्थिक सहयोग दिया करते थे।

नई आर्थिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जाल में देश के संसाधनों पर कब्जा और दोहन हो रहा है। धनी अस्मिता, सांस्कृतिक आजादी, शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा और खाद्य स्वालम्बन सब कुछ दाँव पर चढ़ चुका है। पूँजीवादी साम्राज्यवादी ताकतें नूतन रूपों में हल्ला बोल रहीहैं। सकल घरेलू उत्पाद की पचास फिसदी काला धन अधिपत्य जमा चुका है और नैतिकता को घोल कर पी चुके सफेद पोश नेतों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष-विपक्ष की पार्टियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू भर हैं। वाम ताकतें कमजोर पड़ चुकी हैं और इनके ऊपर विरोधियों के हमल तेज हो चुके हैं तथा जनता त्राहि-त्राहि कर रही हैं परन्तु उसे और उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरकर नेतृत्व देने वाला कोई नहीं हैं।

ऐसे घटाटोप अँधेरे में हमें शहीद-ए-आज़म भगत सिंह और अनय महान क्रान्तिकारियों की आड़ में देशी-विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों को खुली चुनौती देने का वक्त आ चुका है। अभी देश में बहने वाली क्रान्तिकारियों की ऊर्जा की धार सूखी नहीं है। संभवत: ऐसे संकल्प के जरिये देश की तकदीर बदली जा सकती हैं और इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ हाक भी नहीं सकती।

(लेखक प्रभाशंकर मिश्र जी एक स्तंभकार और एक जनसंगठन के सक्रिय सदस्य हैं)

पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा की रक्षा भारत में वामआंदोलन की रक्षा है

प्रकाश करात, महासचिव - सीपीआई (एम)

हमारे देश में पश्चिम बंगाल वाम एवं लोकतांत्रिक आंदोलनों का गढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल ने यह स्थिति लगातार कामगारों एवं किसानों के चलने वाले अनवरत संघर्षों और लोकतांत्रिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा में चलाये जाने वाले आंदोलनों के कारण तैयार हुई थी। उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है कि एक दशक से लम्बे समय तक खाद्यान्न आन्दोलन और भूमि के लिये संघर्ष यहाँ चलता रहा वर्ष 1967 और 1969 में संयुक्त मोर्चे की सरकार का उभार इन्हीं जनप्रिय आन्दोलनों के कारण था। किसानों का भूमि संघर्ष इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में तीव्र हो गया।

पश्चिम बंगाल में लोगों ने कांग्रेस और सत्ताधारी वर्ग के तानाशाही और अर्द्धफांसीवाद के आतंक के विरुद्ध वर्ष 1971 से 1977 तक तेज संघर्ष छेड़ दिया था।

वर्ष 1977 में एक नये अध्याय का उद्गम हुआ और कामगारों तथा लोकतंत्र के लिये लड़ने वाले जांबाजों की वजह से पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे की सरकार का गठन हुआ। वाममोर्चे की सरकार ने कामगारों के हर वर्ग के हीत की रक्षा करते हुये कार्यक्रमों का निर्माण किया। इन कार्यक्रमों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है - भूमि सुधार कार्यक्रम। लगभग 13 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और भूमिहीन गरीब 30 लाख किसानों में वितरित किया गया। ऑपरेशन बर्गा के अंतर्गत 15 लाख बंटाईदारों को अपने कार्य करने के लिये कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई। पूरे देश में कुल सीलिंग सरप्लस भूमि वितरण में अकेले पश्चिम बंगाल का भाग 22 प्रतिशत रहा है। वाममोर्चे की सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया कि उसने बलपूर्वक किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया गया है, परन्तु इसके बावजूद वर्ष 2007 से 2010 के अन्तराल में 16700 एकड़ भूमि का वितरण भूमिहीन परिवारों में किया गया।

पश्चिम बंगाल की तर्ज पर देश के किसी राज्य में भूमि सुधार का कोई उदाहरण सामने नहीं आया। कोई अन्य राज्य आश्वस्त नहीं कर सका कि कृषि विकास का मुनाफा किसानों को मिले न कि मुट्ठी पर धनाढ्य किसानों और जमींदारों को मिले। पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रणाली का

संस्थाकरण किया गया, जिससे मेहनतकश ग्रामीण जनता को भी स्थानीय मामलों में अपनी बात रखने का हक प्राप्त हुआ। लम्बे समय तक वाममोर्चे की सरकार चलने से राज्य में एक स्थायी धर्मनिरपेक्ष माहौल का सृजन हुआ जबकि इस राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद भीषण साम्प्रदायिक हिंसा का दौर झेला था। सभी वर्गों में कामगारों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा वाममोर्चे की सरकार के अंतर्गत दिया गया।

उपर्युक्त बताई गई उपलब्धियों की वजह से वाममोर्चे की सरकार ने लगातार 7 बार विधानसभा चुनावों में दो तिहाई बहुमत हासिल किया।

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा जहाँ एक तरफ राज्य की जनता के हितों की रक्षा के लिये कार्य करता रहा है, वहीं केन्द्र सरकार के नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में भी मुख्य भूमिका निभाता रहा है। ये नवउदारवादी नीतियाँ ही तेजी से चढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी और विकराल होती असमानता के लिये जिम्मेदार है।

आज वाम दलों का यह गढ़ खतरे में है, जिसके ऊपर आक्रमण किये जा रहे है, क्योंकि वामदलों ने लगातार केन्द्र में सत्तासीन कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की उसके नवउदारवादी नीतियों के कारण अपना संघर्ष छेड़ रखा है। इन नीतियों की वजह से मुट्ठीभर लोग धनी हो रहे हैं और देश के संशाधनों की खुली लूट का मार्ग खुल गया है। जिससे देश की विशाल आबादी अभाव गरीबी और गरीबी में जीने के लिये विवश है। वामदलों ने योजनावद्ध तरीके से संप्रग सरकार के अमेरिकी गठजोड़ का विरोध किया है और साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव को ललकारा है। सत्ताधारी वर्ग और साम्राज्यवादी शक्तियों को पता है कि उनके कुकृत्यों को पुरा होने में वामदल सबसे बड़ी मुसीबत है। इस बात का एहसास उन्हें पिछले लोकसभा सत्र में चार वर्ष तक साथ काम करके भली भांति पता चल चुका है। इन चार वर्षों में संप्रग सरकार को वामदलों ने बाहर से समर्थन दिया था क्योंकि ये लोग भारत में वामदलों को कमजोर करना चाहते है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वामदलों के सबसे मजबूत गढ़ पश्चिम बंगाल को उन्होंने लक्ष्य बना रखा है।

वर्ष 2008 से यह स्पष्ट हो गया है कि वामविरोधी ताकतें जिनमें प्रतिक्रियावादी और अति चरम वामपंथी भी शामिल है। वामदलों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तृणमूल – कांग्रेस गठजोड़ जो माओवादियों के साथ तालमेल में चल रहे हैं इन्हें इस रूप में देखा जा सकता है क्योंकि वर्ष 2009 में संपन्न हुये लोकसभा चुनाव के बाद से 17 जनवरी 2011 तक 366 कार्यकर्ता और वामदलों के सहयोगी मारे गये है, हजारों लोग बेघर किये गये है। अनेक किसानों और बंटाईदारों को खदेड़ा गया, पार्टी एवं जनसंगठनों के कार्यालयों को जबरन कब्जा कर लिया गया। ये हमलें उजागर करते है कि वाम मोर्चे के विरुद्ध बने राजनैतिक गठजोड़ का वास्तविक चरित्र क्या है?

माओवादी लोग अति चरमपंथी वाम ताकतें है जो अराजकतापूर्ण हिंसा में लिप्त है। अपने गलत वैचारिक और राजनैतिक सोच के कारण ये लोग अविवेकपूर्ण हिंसा में डूबे हुये है। इस कारण ये लोग उन लोगों के साथ आसानी से हाथ मिला लेते हैं जो हमलोगों के विरोध में है। माओवादियों का तृणमूल कांग्रेस के साथ बना गठजोड़ गिरते हुये राजनैतिक चरित्र का यह एक मजबूत उदाहरण है।

दक्षिणपंथी विपक्षी ताकतें अपने विषाक्त गैर वामपंथी दृष्टिकोण को छुपाने के लिये चेहरे पर वाम का मुखौटा लगा लेते है, क्योंकि उन्हें पता है कि खुले आम वे लोग जनता के बीच में दक्षिणपंथी या प्रतिक्रिया वादी बनकर जनता को गोलबंद नहीं कर सकते हैं। अति चरमपंथी वाम माओवादियों के नारे का प्रयोग तृणमूल कांग्रेस वामदलों को घेरने के लिये प्रयोग में ला रही है।

परन्तु यह वामदलों के ऊपर जारी हमला सही मायने में एक वर्ग संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है और उनकी उपलब्धि जैसी भी हो वह न केवल वाममोर्चा और सीपीआई (एम) के विरुद्ध है बल्कि आम जनता के भी विरोध में है। तृणमूल कांग्रेस गठजोड़ द्वारा वाममोर्चा सरकार के विरुद्ध जारी तथाकथित 'लाल कुशासन' का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने का है और वर्ग संघर्ष के नजरिये से पुन: पूँजीपति, साम्राज्यवादी शक्तियों की स्थापना है। इनके गठजोड़ के द्वारा तथाकथित रूप से 'परिबोरतन (परिवर्तन)' की दुहाई देने के पीछे पुन: प्रभावशाली बुर्जुआ वर्ग की स्थापना का लक्ष्य है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपने निहीत स्वार्थों को देख रहे हैं, और नवउदारवादी नीतियों को सहजता पूर्वक थोपने के लिये बुर्जुआ वर्ग क्रान्तिकारी जनोत्तेजना की धार को कुन्द (भोथर) करना चाहते है।

वाममोर्चा सरकार को सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर अपनी निगाह लगाये ये गठजोड़ पुन: गरीब और ग्रामीण किसानों की जमीन को वापस हथियाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल ने सफलतापूर्वक साम्प्रदायिक ताकतों को हाशिये पर ढकेल दिया है, वे पुन: साम्प्रदायिक राजनीति के द्वारा मुख्य भूमिका में आने चाहेंगे। अवसरवादी बुर्जुआ राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस और अन्य उनके सहयोगी राज्य में पुन: साम्प्रदायिक राजनीति को पैदा करेंगे और वाम शासन के अंतर्गत दशकों से बने हुये साम्प्रदायिक सौहार्द्ध और शांति के वातावरण को चोट पहुँचायेंगे। हाल में ही हमलोगों ने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस ने जातिगत, धार्मिक और क्षेत्र–नस्लवाद की पहचान पर आधारित राजनीति को हवा दी है। चाहे यह मामला गोरखालैण्ड आन्दोलन का हो या कामतापुरी की मांग का हो। ऐसी राजनीति मेहनतकश जनता की एकता को कमजोर करने वाली होती है।

वाममोर्चा सरकार बुजुर्आ–भूस्वामी प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रही है। केन्द्र–राज्य संबंधों के चरित्र और सत्ता का वास्तविक उद्गम केन्द्र के पास होने से वाममोर्चा सरकार को संसाधनों और उर्जा के क्षेत्र में गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। नौकरशाही का चरित्र और राज्य का संस्थागत स्वभाव राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने में बाधक बना करते हैं। वाममोर्चा ने ऐसा भ्रम कभी नहीं किया कि सभी समस्याओं को

वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार हल कर देगी। नवउदारवादी नीतियों के दुष्प्रभाव से जनता के ऊपर भारी असर पड़ रहा है।

तृणमूल-कांग्रेस गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव में वाममोर्चे को मिली हार के विषय को बढ़ा-चढ़ाकर अलोकतांत्रिक तरीके से आक्रमण करता रहा है। वाममोर्चा इसके उत्तर में जनता के बीच में जाकर अपनी अभिव्यक्ति देता रहा है तथा साथ ही अपनी कमियों को दूर कर कार्यकुशलता में सुधार लाता रहा है। पिछले महीनों का अनुभव है कि लगातार चलाये जा रहे राजनैतिक प्रचार और जनता से उसके विषयों पर बढ़ाये गये सहयोग से वाममोर्चा को साकारात्मक दिशा में बढ़ने का मौका मिला है। राज्य की जनता तृणमूल-कांग्रेस गठजोड़ और माओवादियों के साथ उसके घिनौने संबंध के खेल देख रही है।

पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे का संघर्ष दक्षिणपंथी ताकतों से निपटने का जारी है। जैसा कि विदित है कि देश में चले वाम आंदोलनों की विशेष परिणति के रूप में पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा की स्थापना हैं, इसलिये संपूर्ण वाम और लोकतांत्रिक ताकतों को वाममोर्चे के उठाये गये मुद्दों पर कदम से कदम मिलाना चाहिये। पश्चिम बंगाल के बाहर स्थित कामगारों की आबादी भली भांति जानती है कि उदारीकरण और निजीकरण के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की मेहनतकश जनता जोरदार संघर्ष कर रही है। पश्चिम बंगाल का किसान आन्दोलन राज्य के बाहर चल रहे किसान आन्दोलनों को दिशा प्रदान करता है। देश नौजवानों, महिलाओं और छात्रों के लोकतांत्रिक आन्दोलन पश्चिम बंगाल में चल रहे आन्दोलनों की तरफ सहयोग की आशा से टकटकी लगाये रहते है।

इस तरह देश की सभी वाम और लोकतांत्रिक शक्तियों का कर्त्तव्य बन जाता है कि वे पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार के पक्ष में सहयोग दें।

हमें पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा और वहाँ चल रहे लोकतांत्रिक आन्दोलनों को भरपूर ताकत के साथ देना होगा। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और समाजवाद की लड़ाईन लड़ने वाले बहादुरों के लिये संदेश देना जाना चाहिये कि पूरे देश की प्रगतिवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का पूरा-पूरा सहयोग उनके साथ है।

23 फरवरी 2011 को मेहनतकश जनता नई दिल्ली में सैलाब

नई दिल्ली, 23 फरवरी 2011 को नई दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनता व पुलिस मेहनतकश जनता की संख्या का सही अनुमान लगाने की उधेड़ बुन में लगे हुये थे जिन्होंने राजघाट, रामलीला मैदान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संसद घेरने के लिये आईटीओ, कनॉट प्लेस, बाराखम्बा रोड़, होते हुये मार्च किया। हर ओर से 2 से 3 किलोमीटर तक के के लम्बे इस मार्च के कारण चारों ओर से ट्रेफिक जाम की समस्या गंभीर बन गई थी। इस प्रस्ताविक मार्च में दिल्ली पुलिस ने आंकड़ा दिया लगभग 1.5 लाख लोगों ने मार्च में भाग लिया, जबकि हकीकत में यह आंकड़ा उनके इस अनुमान से कई गुणा ज्यादा था।

मेहनतकश की इस मार्च में भागीदारी कों भावनाओं से ऐतिहासिक बनाती है, पहली – यह पहले से ही निर्धारित था कि मार्च प्रात: 11 बजे से आरंभ होगा और संसद पर 12 बजे दोपहर पहुँचेगा, लेकिन यह जनसमूह प्रात: 8 बजे ही श्रृंख्लावद्ध तरीके से लाईन में खड़ा हो गया तथा ट्रेड यूनियन नेताओं को मजबूर कर दिया कि मार्च का आरंभ प्रात: 9.30 बजे किया जाये, दूसरा – चाईनिज बैनर, लाल झण्डे, इश्तिहार रूपी गहनों आदि से लाईनें सजी हुई थी और तीसरा – मेहनतकश जनता ने मार्ग पर मार्च करते हुए पूर्ण संयम का प्रदर्शन किया।

दिल्ली वासियों के लिये यह दृश्य कई वर्षों के बाद देखने को मिला। मेहनतकश मजदूरों के इस विशाल सागर में देश के हर कोने से छोटी-छोटी मेहनकश आवाम नदियों ने भाग लिया ताकि वे इस बेहरी हो चुकी कांग्रेस नेतृत्व संप्रग सरकार को अपनी आवाज पहुँचायी जा सके। इस रैली के आयोजन का निर्णय केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा कई औद्योगिक फेडरेशनों संगठित व असंगठित क्षेत्र के संगठनों के संयुक्त सभा में 7 सितम्बर 2010 को लिया था। संसद मार्च में शामिल होने के लिये मजदूर 20 फरवरी से ही राजधानी पहुँचने लगे थे और 23 फरवरी आने तक दिल्ली इस तरह जाम हो गयी थी कि उनके ठहरने के लिये कोई रिक्त स्थान दिल्ली में बचा था। जबकि एक विशाल जन समूह तो भारतीय रेल के लेट लतीफी की वजह से दिल्ली देर तक पहुँची। लाखों मजदूरों के रूकने की व्यवस्था करना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो गया था, लेकिन इन मजदूरों का जज्बा जिन्होंने अपने सुख को काटकर दूसरों को सुख का हमेशा ख्याल रखा है, उन्हें इन तकलीफों का तनिक भी मलाल नहीं दिख रहा था, बल्कि वे और भी जोश-खरोश से भरे हुये थे। लाल-लाल टोपियों, रंग-बिरंगें बैनरों, लाल झण्डों मजदूर एकता जिन्दाबाद व संप्रग विरोधी नारे लगाते हुये आगे बढ़ रहे थे। जुलुस की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें लाखों की संख्या में महिला मजदूरों ने भी भाग लिया। इस रैली का नेतृत्व साथी एस.पी. तिवारी (टीयूसीसी), साथी गुरूदास दासगुप्ता (एआईटीयूसी), साथी तपन सेन (सीआईटीयू), साथी उमरावमल पुरोहित (एचएमएस), साथी संजीवा रेड्डी (आईएनटीयूसी), साथी स्वपन मुखर्जी (एआईसीसीटीयू), साथी शंकर साहा (एआईयूटीयूसी) और अन्य क्षेत्रों, फेडरेशनों आदि के नेताओं ने एक संयुक्त बैनर के तले किया।

मजदूरों का यह मार्च संसद मार्ग पर बने मंच के सामने एकत्रित हो गया। इस रैली के आयोजनकर्ता सभी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों व अध्यक्षमंडली

ने मंच का संचालन किया। इस रैली को मुख्य रूप से साथी जी.आर. शिवशंकर (टीयूसीसी), साथी ए.के. पद्मनाभमन (सीआईटीयू), साथी प्रमोद गोगोई (एआईटीयूसी), साथी के.वी. थोमस (एआईसीसीटीयू), साथी कृष्णा चक्रवर्ती (एआईयूटीयूसी), साथी आर.ए. मित्तल (एचएमएस), साथी अबनी रॉय (यूटीयूसी) आदि नेताओं ने किया। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के नेताओं ने देश की वर्तमान आर्थिक-सामाजिक और आद्योगिक नीति पर कही तथा यह कहा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कारपोरेट घरानों को देश की प्राकृतिक संसाधनों और खादानों को लूटने की छूट नहीं मिलनी चाहिये। इसके अलावा इनके द्वारा मजदूरों पर किये जा रहे शोषण, हिंसात्मक कार्यवाही के सख्त कदम उठाने चाहिये तथा देश में मजदूर कानून का कड़ाई से लागू करना चाहिये। साथी संजीवा रेड्डी, सांसद (अध्यक्ष आईएनटीयूसी) ने पीड़ित मजदूरों से आह्वान किया कि उन्हें वाम ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर एकजुटता के साथ संघर्ष करना चाहिये, उन्होंने यह भी घोषणा किया की भविष्य में भी संयुक्त रूप से इस संघर्ष में साथ रहेंगे। साथी गुरूदास दासगुप्ता, सांसद (महासचिव एआईटीयूसी) ने सरकार पर बरसते हुये कहा कि कि आज देश का "आम आदमी" इस बढ़ती महँगाई से बुरी तरह परेशान है। साथी तमपन सेन (महासचिव सीआईटीयू) ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश बन्द करें और देश को ध्रुवीय मन्दी से बचाये।

साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव, टीयूसीसी ने देश के कोने-कोने से आये तमाम मजदूरों का संसद मार्ग पर एकता प्रदर्शन के लिये धन्यवाद दिया। बढ़ती महँगाई, एक के बाद एक घोटाले करने वाली, मजदूर कानून की अवहेला करने वाली, देश की प्राकृतिक संपदा को लूटने वाली सोई हुई सरकार को जगाने के लिये एकता का परिचय दिया है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से ऊँची आवाज में पुछा कि राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा मांगों को मानेंगे या दिल्ली को भी 'मिस्र के तहरीर स्क्वेयर' बनाना चाहते है। उन्होंने सभी राजा, महाराजाओं को दण्ड देने की मांग की, जिन्होंने 2जी और 3जी स्पेक्ट्रम घोटाले किये राष्ट्रमण्डल खेल में लूट की। उन्होंने आगे कहा कि - सरकार ने कारपोरेट घरानों को हमारी जमीनी और जमीन के ऊपरी संपदा को कैसे बेच दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 'हमारी सुन लो अन्यथा जाना होगा'।

टीयूसीसी ने इस कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आदि से आये टीयूसीसी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था और एक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का देश भर में 'बंगाल अभियान'

नई दिल्ली में आयोजित 7 व 8 फरवरी 2011 अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग के निर्णयानुसार पार्टी ने 19 से 25 फरवरी तक देश भर में 'बंगाल अभियान' चलाया गया।

मई व जून माह में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह अभियान आवश्यक हो गया था, जब सभी प्रतिक्रियावादी ताकतें, चरमपंथी ताकतों एवं खण्डित ताकतों के साथ मिलकर - जिसमें निजी स्वार्थी ताकतें - कारपोरेट हाउस, विदेशी पूँजीपति और दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक वाममोर्चे की सरकार को खत्म करने विशेषकर पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे का समाप्त करने का घिनौना षड्यन्त्र रच रहे हैं। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने संकल्प किया कि इन विरोधियों द्वारा किये जा रहे हमले और धमकी के प्रति देश भर में अभियान चलाकर जनता के बीच में आवाज उठायेगी तथा उनके अन्दर राजनैतीक चेतना जगायेगी तथा वाम व वामंथी ताकतों को सहयोग देने का आग्रह करेगी।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का मत है कांग्रेस की अनैतनिक शासन व्यवस्था और उसके साम्राज्यवादी एजेंटों तथा पूँजीपतियों की शोषणकारी रवैये से पश्चिम बंगाल को बचाये रखने के लिये संघर्ष का ही परिणाम है कि वहाँ वामपंथ की सरकार कायम है। वामपंथी सरकार ने जनहित में कार्य करने की एक अद्भुत मिसाल पेश किये जैसे - व्यापक भू-सुधार, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण विकास, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता आदि। पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक वाममोर्चा सरकार को बदनाम करने के लिये हर तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से, मक्कारी से, आदि सभी हथकंडे इस्तेमाल किये जा रहे है और अस्थिर करने की चाल चली जा रही है। इसके लिये दक्षिणपंथी अराजक शक्तियाँ चरमपंथी वाम को ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक फैलाने के लिये, आदिवासियों और गामिण कार्यकर्ताओं को मारने के लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। अत: प्रगतिशील और भारत की लोकतांत्रिक जनता का यह नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि बंगाल की विपक्षी पार्टी, केन्द्र सरकार, कारपारेट हाउस, साम्राज्यवादी एजेंटों और माओवादियों के घिनौने चेहरे को उजागर करने की पहल करें।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की सभी राज्य इकाईयों - महाराष्ट्र, झारखण्ड, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा व अन्य राज्यों में धारना प्रदर्शन, जनसभा और प्रदर्शनियों का आयोजन करते हुये वामविरोधी धमकियों के प्रति जनता को जताया तथा पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया।

महाराष्ट्र में बंगाल अभियान : 19 फरवरी 2011 टीयूसीसी ने पुणे के पिम्परी में एक सभा का आयोजन किया। जिसमें मुख्य वक्ता साथी डॉ. बरूण

मुखर्जी जी, सांसद थे। अन्य वक्ताओं में साथी अरूण वांकर (महासचिव फारवर्ड ब्लॉक महाराष्ट्र राज्य कमेटी), साथी के.आई.पी. मेनन (टी.यू.सी. सी. नेता), साथी शिंदे, साथी शिलोटे आदि थे। वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों के मद्देनजर वक्तव्य देते हुये कहा कि किस प्रकार वामफ्रंट पर अराजक ताकतें उन्हें हराने के लिये षड्यन्त्र रच रही है। जिसके लिये दक्षिणपंथियों और चरमपंथियों ने गठजोड़ बना लिया है। महाराष्ट्र की जनता अपना सहयोग वामफ्रंट के लिये करें।

दूसरी सभा का आयोजन सत्यवादी भवन, हाजी अली के पास, तारदेव, मुम्बई में 20 फरवरी 2011 को आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी देखने योग्य थी। मुख्य वकता फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय सचिव साथी डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद थे, अन्य वक्ताओं में ऑल इण्डिया यूथ लीग नेता साथी सतीश राज शिरके, अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की नेत्री साथी सीमाराजे शिरके, फारवर्ड ब्लॉक के साथी अरूण वांकर, टीयूसीसी नेता साथी दिलीप तावडे, सखाराम भोसले, साथी नदीमभाई आदि थे। सभी वक्ताओं ने कहा कि देश की सभी जनता को अब एकजुट होकर वाम मोर्चा पर हो रहे हमले की विशेषकर पश्चिम बंगाल में हो रहे हमले की निंदा करनी चाहिये।

तीसरी सभा का आयोजन हिन्दी साहित्य सम्मेलन सभागृह, सीतानारडी, नागपुर में हुआ। सभा को साथी डॉ. मुरतोजा हुसैन, पश्चिम बंगाल फारवर्ड ब्लॉक नेता ने सम्बोधित किया। अन्य वक्ताओं में साथी धरमराज दुबे, साथी अरूण वांकर, साथी बलवंत राय मेहता, अग्रगामी महिला समिति की नेत्री साथी पूर्णिमा बिश्वास, साथी सोफिया सुल्ताना, साथी राधिका हेडाव आदि थे।

झारखण्ड में बंगाल अभियान: बंगाल अभियान के तहत 21 फरवरी 2011 को बंगाल धनबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय सचिव साथी बीर सिंह महतो, सीपीआई (एम) सचिव साथी ज्ञान शंकर, सीपीआई साथी गोपीनाथ बक्शी के अलावा झारखण्ड राज्य कमिटी फारवर्ड ब्लॉक के नेतागणों में साथी शानु चौधरी, साथी मोफिज साहिल, गौतम सेनगुप्ता, साथी बी. प्रसाद, साथी फातीमा खातुन, साथी कल्याण बक्शी आदि थे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि दक्षिणपंथी व देश की अराजक शक्तियां मात्र पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार पर ही हमला नहीं कर रही हैं बल्कि वाम दलों पर देश भर में उन पर हमले कर रहे हैं। देश की जनता को एकजुटता के साथ वाम दलों का सहयोग करके इस षड्यन्त्र को विफल करना होगा।

विस्थापन की समस्याओं का हल निकालो

झारखण्ड: 14 मार्च 2011 को वामपंथी दलों ने विधानसभा मार्च निकाला तथा यह मांग किया कि सी.एन.टी. एक्ट एवं एस.पी.टी एक्ट को सख्ती से लागू करो।

झारखण्ड राज्य बनने से यह उम्मीद जगी थी कि झारखण्ड का जंगल, जमीन, जल सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो पाएगी लेकिन वर्तमान अर्जुन मुण्डा सरकार सहित पिछली सभी सरकारें इसमें विफल रही। झारखण्ड क्षेत्र में अँग्रेज सरकार के समय से ही शुरू जमीन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की लूट अब तक जारी है।

साम्राज्यवादी अँग्रेजी हुकूमत के औपनिवेशिक काल में बलात भू-अर्जन के लिए कानून बनाया गया। ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भू-अर्जन कानून 1894 के माध्यम से झारखण्ड के किसानों की 'खूंटकट्टी' एवं 'कोड़कर' भूमि पर कब्जा कायम किया गया। इसी भूमि अधिग्रहण कानून की आड़ में हजारों-हजार ग्रामीणों को भूमिहीन, गृह-विहीन, साधन-विहीन बनाकर उन्हें दर-दर का भिखारी बनने को मजबूर किया गया। इसी भूमि लूट के विरोध में 1895 में बिरसा - उगुलान प्रारंभ हुआ। यह उलगुलान भूमि लूट-विस्थापन के खिलाफ तथा स्वशासन की वापसी के लिये था

आजादी के बाद उक्त भू-अर्जन कानून को थोड़ा बहुत संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया और उसमें 'विकास' शब्द जोड़ दिया गया। इस विकास ने लाखों झारखण्डियों को विनाश एवं बर्बादी के गर्त में ढकेल दिया। इस विकास के क्रम में हटिया परियोजना, बोकारो परियोजना, डी.वी. सी., कोनार डैम, तिलैया डैम, बोकारो थर्मल पावर, चन्द्रपुर थर्मल पावर, चांडिल डैम, मैथन डैम, टाटा-टिस्को-टेल्को कारखाना के नाम पर लगभग 32 लाख झारखण्डियों को घर से बेघर कर दिया गया। इस विस्थापन की मार से उजड़े झारखण्डियों को बाध्य होकर अन्यत्र पलायन की मार से उजड़े झारखण्डियों को बाध्य होकर अन्यत्र पलायन करना पड़ा और दाई-नौकर एवं रेजा-कुली बनना पड़ा। अब तक झारखण्ड सरकार के साथ निजी कम्पनियों तथा उद्योगपतियों का एक सौ से ज्यादा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो चुके है। इनकी गिद्धदृष्टि झारखण्ड के अकूत खनिज सम्पदा पर टिकी है।

अब सरकार खुद सी.एन.टी. एक्ट पर राजनीति करने लगी है। एक तरफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने 4 दिसम्बर 2010 को भू-राजस्व से सम्बन्धित पदाधिकारियों के नाम पत्र जारी किया कि सी.एन.टी. एक्ट की धारा 46(1) प्रोविजन (बी) के अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किसी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े जाति के लोगों की रैयती भूमि का का हस्तान्तरण उपायुक्त की अनुमति के बिना

नहीं किया जाये और कोई दाखिल खरिज नहीं किया जाये। दूसरी तरफ 11 दिसम्बर 2010 को सरकार के विशेष सचिव ने अपने पत्र से 4 दिसम्बर 2010 के पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

सी.एन.टी. एक्ट एवं एस.पी.टी. एक्ट के साथ छेड़-छाड़ करने की इस साजिश के खिलाफ वाम दलों द्वारा 14 मार्च को विधानसभा मार्च किया जायेगा। मार्च के दौरान निम्न मांगों की गई:

1. विस्थापन एवं सी.एन.टी. एक्ट के मुद्दे पर अविलम्ब सर्वदलीय बैठक बुलायी जाये।
2. अ-पुनर्वासित विस्थापितों के पुनर्वास के लिए अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष आयोग का गठन किया जाये।
3. रैयतों के पुनर्वास, पुनर्स्थापना और कानूनी हक दिलाने के लिए भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2007 और पुनर्वास पुर्नस्थापना विधेयक 2007 को संसदीय स्थायी समिति के संशोधन के साथ पारित करो।
4. आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्गों को जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए सी.एन.टी. एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करो।
5. सी.एन.टी. एवं एस.पी.टी. एक्ट को कमजोर करने के सारे प्रयासों को बन्द करो।
6. अब तक हुए 107 एम.ओ.यू. को अविलम्ब रद्द करो।

रैली का आयोजन फारवर्ड ब्लॉक, सीपीआई (एम), सीपीआई एवं आरएसपी ने संयुक्त रूप से किया। यह रैली राँची रेलवे स्टेशन से चलकर विधानसभा तक पहुँची।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) के महाधिवेशन में साथी जनार्दन पाण्डेय ने भाग लिया

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) के आठवें महाधिवेशन में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की ओर से केन्द्रीय सचिव मण्डल सदस्य साथी जनार्दन पाण्डेय ने भाग लिया। नेपाल के जनकपुर धाम में नेकपा (संयुक्त) का राष्ट्रीय महाधिवेशन 15, 16, 17 एवं 18 फरवरी 2011 को संपन्न हुआ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) के आठवें राष्ट्रीय महाधिवेशन के खुले सत्र को सम्बोधित हुऐ साथी पाण्डेय ने कहा कि भारत एवं नेपाल की जनता के रिश्ते काफी पुराने एवं गहरे हैं। हम दोनों देशों की हित एकजुटता की कामना करते हैं। आज साम्राज्यवादी शक्तियों के बढ़ते मंसूबों को चकनाचूर करने के लिये वृहत्तर वाम जनवादी एकता को मजबूत करने की जरूरत है। साम्राज्यवादी ताकतें भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण के जरिये वैश्विक शांति, भाईचारा एवं लोकतंत्र पर चतुर्दिक हमला कर रही है जिससे मुकाबला करने के लिये वाम जनवादी ताकतें मजबूत अवरोध के रूप में खड़ी हो रही हैं। एशिया महादेश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में वाम शक्तियों को कमजोर करने के लिए विश्व साम्राज्यवाद तरह-तरह के हथकण्डे अपना रहे हैं। वाम जनवादी ताकतों का भारतीय रॉल मॉडल पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को अस्थिर कर वाम आन्दोलन, किसान मजदूर एवं मेहनतकश आवाम पर हमला कर रहे है।। दुनियाँ के महान क्रांतिकारी एवं अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाषा चन्द्र बोस ने साम्राज्यवाद का सूर्यास्त होने वाल है लेकिन विश्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद का नया संस्करण आयेगा। नेताजी ने दुनिया के वाम जनवादी एवं मेहनतकश आवाम से साम्राज्यवाद विरोधी समझौता विहीन संघर्ष की मशाल को तेज करने का आह्वान किया था।

साथी पाण्डेय ने कहा कि नेकपा (संयुक्त) के आठवें राष्ट्रीय महाधिवेशन इस दिशा में ठोस प्रस्ताव ग्रहण करेगा।

साथी पाण्डेय ने कहा कि इसी ऐतिहासिक जनकपुर धाम में राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने का कठिन संकल्प ग्रहण किया था एवं दुनिया के विस्तारवादियों का मानमर्दन हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आठवाँ महाधिवेशन से दुनियाँ के अमन पसन्द जनता को एक ठोस संदेश जायेगा।

अधिवेशन का उद्घाटन नेकपा (संयुक्त) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड चन्द्रदेव जोशी ने किया। अधिवेशन में माले वेसस के कामरेड इन्द्र कुमार झा, नेकपा (माले) पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड गोपालमणि गौतम, नेपाल सद्भावना पार्टी के कामरेड आनन्दी देवी, कामरेड खुशीलाल मण्डल, राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी के चन्द्रशेखर यादव, नेकपा एमाले के केशव देव कोटा, राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल कामरेड रश्मि राज नेपाली, नेकपा संयुक्त नेता कामरेड गणश साह, कामरेड किशोरी साह, कामरेड विष्णु बहादुर मालंकर, विश्वनाथ भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुपीम कोर्ट, आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये।

टी.यू.सी.सी. एवं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्ल्यू.एफ.टी.यू.) ने

लिबिया पर अमेरिकी हमले की निंदा की

भारतीय परतंत्रता के समय में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी मातृभूमि के लिये अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गैर समझौतावादी राष्ट्रीय व क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जी ने भविष्यवाणी ने किया था बीसवीं श्दी के आने वाले दिनों में अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनिया पर छा जायेगा। जो बेशक आज सिद्ध हो चुका है। अमेरिकी के नेतृत्व में लिबीया की जनता की यादगार गरिमा पर जारी बर्बर साम्राज्यवादी ताकतों के हमलों की टी.यू.सी.सी. व डब्ल्यू.एफ.टी.यू. पुरजोर विरोध करता है।

पूर्वी भू–मध्य, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका की प्रगति साम्राज्यवादी ताकतों के सामने प्रतिस्पर्द्धात्मक रूख से साम्राज्यवादी ताकतों विचलित है। अत: ये साम्राज्यवादी ताकतें लिबीया के पेट्रोलियम भण्डार, उत्तरी अफ्रीकी देशों के प्राकृतिक गैसों और कच्चे पदार्थों पर अपना हक काबिज करने का मंसूबा संजोये हुये हैं।

आर्थिक नेतृत्व की प्रतिस्पर्द्धा के कारण छद्म युद्ध या पूर्णयुद्ध का माहौल बना रहता है, जैसा कि आजकल लिबीया में हो रहा है।

यूरोपीयन संघ, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड और उनके सहयोगी यह तर्क दे रहे हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र के निर्णय का पालन कर रहे हैं।

वे अब्बल दर्जे के पाखण्डी और झूठे है।

अगर ऐसा है तो साईप्रस मुद्दे पर प्रस्तावित प्रस्ताव पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ? संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मुद्दें पर प्रस्तावित प्रस्तावों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्यूबा पर पाबंदी हटान की संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

हम मांग करते हैं कि लिबीया पर जारी सैनिक कार्यवाही को तुरन्त रोका जाये। हम लिबीया की जनता के साथ अंतराष्ट्रीय एकजुटता व्यक्त करते हैं।

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का 16वाँ वर्ल्ड ट्रेड यूनियन महासम्मेलन, एथेंस, ग्रीस में 6 से 11 अप्रैल 2011 तक

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का 16वाँ वर्ल्ड ट्रेड यूनियन महासम्मेलन, का आयोजन एथेंस, ग्रीस में 6 से 11 अप्रैल 2011 तक होगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्ल्यू.एफ.टी.यू.) का ट्रेड यूनियन को–ऑर्डिनेशन सेन्टर (टी.यू.सी.सी.) सहबद्ध सदस्य होने के नाते एथेंस आने का न्यौता प्राप्त हुआ। 9 फरवरी 2011 को बंग भवन, नई दिल्ली में आयोजित टी.यू.सी.सी. की केन्द्रीय कमेटी ने इस न्यौता को स्वीकार किया तथा टी.यू.सी.सी. ने साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव टी.यू.सी.सी. की अगुवाई में चार सदस्यीय प्रतिनिधी दल भेजने का निर्णय लिया, जिसमें अन्य सदस्य होंगे साथी जी.आर. शिवशंकर, अध्यक्ष टी.यू.सी.सी. एवं उपाध्यक्ष इंटरनेशन ट्रेड यूनियन, एशिया होटल एवं टुरिज्म, साथी के.आई.पी. मेनन, सचिव टी.यू.सी.सी. एवं महासचिव एन.पी.डी.ई.एफ. और साथी पी.एन. द्विवेदी, सचिव मुख्य कार्यालय टी.यू.सी.सी. एवं संयोजक राष्ट्रीय प्रगतिशील निर्माण मजदूर फेडरेशन।